



धमाका डिस्काउंट ऑफर

Exchange & Finance Available

Zelo Electric Scooter

Maa Bhagwati Services & Enterprises
B. No. 23, Infront of IDBI Bank,
Neemuch 9407423966, 8770664866

Commodity:	Gold 99,735	Silver 97,000	Crude Oil 5,963	Natural Gas 302.20	Aluminium 232.30	Copper 827.35
------------	-------------	---------------	-----------------	--------------------	------------------	---------------

अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो EV चलेगी, उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया - पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी संयंत्र में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के प्रोडक्शन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने सुजुकी की इलेक्ट्रिक व्हीकल ई-विटारा को भी हरी झंडी दिखाई।

पीएम ने इस मौके पर कहा, 'आज से भारत में बनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट की जाएंगी। इसके साथ ही, आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोल



मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत हो रही है। यह दिन भारत और

जापान की दोस्ती को भी एक नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों, जापान और सुजुकी कंपनी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

निवेशक हो जाएं कम्प्यूज, किस राज्य में निवेश करें - उन्होंने कहा, 'भारत की सफलता

की कहानी के बीज करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मैंने मारुति सुजुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। हमारे तब के प्रयास आज देश के संकल्पों को पूरा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो EV चलेगी, उसमें लिखा मेड इन इंडिया।'

पीएम मोदी ने कहा, 'मैं सभी राज्यों को निमंत्रण देता हूं। आइए, रिफॉर्स की स्पर्धा करें, प्रो डेवलपमेंट नीति की स्पर्धा करें, गुड गवर्नेंस की स्पर्धा करें। 2047 तक विकसित भारत बनाने

की गति को और तेज करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।'

हमारे हर पार्टनर के लिए विन-विन सिचुएशन - पीएम मोदी ने कहा, 'भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है।

भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास स्कील्ज वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल भी है। इसलिए ये हमारे हर पार्टनर के लिए विन-विन सिचुएशन बनाता है। आज सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और यहां बनी गाड़ियां वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही हैं। यह भारत और जापान के रिश्तों की मजबूती का प्रतीक तो है ही, साथ ही भारत को लेकर ग्लोबल भरोंसे को भी दर्शाता है।

प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर रहेगा अवकाश, कैबिनेट का फैसला

भोपाल। मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। यह फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। आत्म निर्भर भारत के लिए स्वदेशी को अपनाता होगा। मिट्टी गोबर के गणेश बनाने वालों से संपर्क किया है। भारत खिलौने बनाने में विश्व में आगे बढ़ा है।

उन्होंने कैबिनेट की निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में निकाय अध्यक्ष के डायरेक्ट चुनाव कराएंगे। अविश्वास प्रस्ताव के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, अगली कैबिनेट के लिए। प्रदेश के सभी थाने सीसीएनटीएस प्रोजेक्ट के तहत छोटे टेबलेट साथ में लेकर जांच करने जाएंगे। एनलाइन पंचनामा से लेकर जांच की जाएगी। जीपीएस आधारित होगा टेबलेट। 1732 टेबलेट खरीदे जा रहे 25 हजार का लक्ष्य है। पुलिस को प्रशिक्षण दिया जायेगा। 75 करोड़ शुरूआती लागत है। अतिरिक्त लोक अभियाजन सहित 610 कर्मचारी पद सृजन 60 करोड़ 24 लाख 672 करोड़ व्यय होंगे। ताप विद्युत गृह के लिए कोयला उपलब्ध कराने भारत सरकार के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाएंगे। ग्रीड शू परियोजना ला रहे हैं। कोयले को संग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश जल निगम के तहत नल जल योजना के तहत बिजली आपूर्ति के लिए सोलर प्लांट और विंड एनर्जी प्लांट लगाएंगे। 100 और 60 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे।

उज्जैन इंदौर पीथमपुर तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को मेट्रो के लिए डीपीआर बना रहा है। यह 84 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट होगा। जीतू पटवारी के महिलाओं के ज्यादा शोख पीने वाले बयान पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं धार्मिक हैं। जीतू पटवारी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं।

उज्जैन इंदौर पीथमपुर तक दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को मेट्रो के लिए डीपीआर बना रहा है। यह 84 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट होगा। जीतू पटवारी के महिलाओं के ज्यादा शोख पीने वाले बयान पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं धार्मिक हैं। जीतू पटवारी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं।

स्थान - फॉरवर्ड बेंडिंग में 5वां स्थान, नेहा गुर्जर - सुपाइन में चौथा स्थान व पारंपरिक में पौंचवौं स्थान प्राप्त किया।

भोपाल में उपस्थित योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती प्रज्ञा श्रीमाल ने सभी प्रतिभागियों को बधाई! प्रदान कर हमारे नीमच जिले की स्वर्ण पदक विजेता मोनिका मेहता, राज कुमारी गिडवानी और भवना गिडवानी को राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए चयनित होने पर विशेष बधाई प्रदान कर टीम NYSA के विजय होतवानी, आदित्य राज सिंह, रवि पोरवाल, शबनम खान, राधेश्याम मित्तल, बालकृष्ण सोलंकी, पुष्पराज साहू एवं सभी सहयोगियों की प्रशंसा की।



भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में योगासन का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया जिसमें भावना गिडवानी ने सुपाइन श्रेणी में स्वर्ण पदक, राजकुमारी गिडवानी ने बैक बेंडिंग में तीसरा स्थान - फॉरवर्ड बेंडिंग में चौथा स्थान, हेमा पटेल - पारंपरिक श्रेणी में चौथा स्थान, रिमझिम गर्ग - सुपाइन में चौथा

पदक तथा रमा सौरभ जिंदल - टिवस्टिंग बॉडी इंडिविजुअल में कांस्य पदक व - फॉरवर्ड बेंडिंग में 5वां स्थान, रक्षा डांगी - बैकवर्ड बेंडिंग में तीसरा स्थान - फॉरवर्ड बेंडिंग में चौथा स्थान, हेमा पटेल - पारंपरिक श्रेणी में चौथा स्थान, रिमझिम गर्ग - सुपाइन में चौथा

मोरवन जलाशय में केज स्थापित कर, करें मछली पालन, आवेदन आमंत्रित

नीमच 26 अगस्त (निप्र)। सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री देव शाह इनवाती ने बताया, कि जिले में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोरवन जलाशय में केज (पिंजरे नुमा पानी में तैरता हुआ ढाँचा) स्थापित कर मछली पालन के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। केज की स्थापना जिला पंचायत स्वामित्व के ऐसे जलाशयों में किया जाना है जिनका जलक्षेत्र 100 हैक्टेयर से अधिक हो, ग्रीष्म ऋतु में जलस्तर की गहराई कम से कम 20 फिट रहती हो, मोरवन जलाशय केज स्थापित कर मछली पालन योग्य है। जिसमें इच्छुआ मत्स्य सहकारी समिति, सप्तह, ठेकेदार, व्यापारी, एंजेंसिया स्वयं के व्यय से केज स्थापित कर मत्स्य पालन कर सकती हैं। प्रशासन द्वारा आवेदकों को केवल जलक्षेत्र उपलब्ध कराया जायेगा। अनुदान का प्रावधान नहीं है।

राज्य योगासन खेल चैंपियनशिप 2025-26 में नीमच की प्रतिभाओं ने प्राप्त की उपलब्धियाँ

प्रथम बार मिले अवसर में ही राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स में हुआ चयन, अब खेलेंगी नीमच की बेटियाँ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

नीमच 27 अगस्त (निप्र)। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिला नीमच के तत्वावधान में टाउन हॉल में पहली बार आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 20 से अधिक प्रतिभाओं ने भाग लिया था जिसमें प्रदेश स्तर पर भोपाल में दिनांक 23 व 24 अगस्त को आयोजित योगासन स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में नीमच जिले से सीनियर ग्रुप में भूमिका मेहता, राहुल चौधरी, रिमझिम गर्ग ने सीनियर A ग्रुप में अजय सरदार, नेहा गुर्जर, रक्षा डांगी ने सीनियर ब ग्रुप में मोनिका मेहता तथा सीनियर सी ग्रुप में रमा सौरभ जिंदल, भावना गिडवानी, हेमा पटेल और राजकुमारी गिडवानी ने भाग लिया। नीमच की प्रतिभाओं ने

रेडक्रास चुनाव स्थगित करने का जिला कांग्रेस ने किया विरोध

रैली निकाल लगाए वोट चोर-वोट चोर के नारे, भारतमाता को अर्पित किया ज्ञापन

नीमच। रेडक्रास नीमच के चुनाव मतदान के बाद स्थगित करने का कांग्रेस ने मंगलवार को जयभर विरोध किया। मामले में प्रशासन पर सत्तापक्ष के नेताओं और जनप्रतिनिधियों के दबाव में रेडक्रास के चुनाव स्थगित करने का आरोप लगाया है और रैली निकाल वोट चोर-वोट चोर के नारे लगाए और पोस्टर लहराए। साथ ही भारतमाता को ज्ञापन भी अर्पित किया गया। मतगणना को रोक सोमवार देर रात्रि में लोकतंत्र का गला घोट कर रेडक्रास सोसायटी नीमच के चुनाव प्रशासन ने आपत्तियों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिए थे, जिसके विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में एकत्र कांग्रेसजनों ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती के नेतृत्व गांधी भवन से विरोध रैली निकली, जिसमें कांग्रेसजनों ने हाथों में वोट चोर, वोट चोर सहित विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां और पोस्टर थाम रखे थे। इस दौरान कांग्रेसजनों ने जयभर नारेबाजी भी की। रैली गांधी भवन से शुरू हुई जो विजय टॉकीज चौराहा होते ही फोरजीरो चौराहा पहुंची। जहां भारत माता की प्रतिमा को ज्ञापन अर्पण किया



गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने कहा कि जिला प्रशासन की मिली भगत से रेडक्रॉस चुनाव स्थगित किए गए हैं इसलिए यह ज्ञापन जिला प्रशासन को देने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए रेड क्रॉस चुनाव स्थगित करने के विरोध का यह ज्ञापन भारत माता के चरणों में अर्पित किया जा रहा है। प्रशासन ने सत्ता के दबाव में यह फैसला लिया है। बाहेती ने नीमच रेडक्रॉस चुनाव में संचालन करने वाले पीठासीन अधिकारी एसडीएम संजीव साहू को तत्काल निर्लंबित करने की भी मांग करी।

जिला कांग्रेस के ज्ञापन में बताया कि नीमच रेडक्रास सोसायटी के चुनाव 16 वर्षों

के बाद 25 अगस्त 2025 को सम्पन्न हुए, लेकिन जो चुनाव नीमच जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन उनके द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी एसडीएम द्वारा साधारण सभा की सहमति व शासन के नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपन कराए थे, लेकिन मतगणना के शुरू होने के पूर्व आचानक आपत्तियों का हवाला देकर भारी राजनीतिक दबाव के कारण प्रशासन को कोई निर्णय नहीं कर मत पेटियों को खोलकर मत पत्रों के बंडल भी बना लिये गए थे, लेकिन एन वक्त पर जिला कलेक्टर द्वारा भाजपा के दबाव में बनकर निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि भारत

जैसे लोकतान्त्रिक देश मे किसी भी संस्था का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन ही उसकी विश्वसनीयता की नींव होता है जब यह संस्था मानवीय सेवाएं रक्तदान और जनकल्याण के कार्यों से जुड़ी हो तो उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। रेडक्रॉस सोसाइटी नीमच का चुनाव यदि राजनीतिक हस्तक्षेप से स्थगित हो जाए तो यह केवल एक संगठन का संकट नहीं है बल्कि लोकतान्त्रिक मूल्यों पर भी सीधा आघात है। रेडक्रॉस जैसी संस्थाएं तब ही राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर जनता की सेवा कर सकती है, जब वह सेवाभाव और निष्पक्षता पर आधारित हो न कि राजनीतिक लाभ हानि पर होता

है। लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र संस्थाओं में बसती हैए यदि उन्हें राजनीति की जकड़ में बांध दिया गया तो जनता का भरोसा टूटेगा और लोकतंत्र का स्वरूप खोखला हो जाएगा।

इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण बाहेती, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौरसिया, प्रदेश सचिव सत्यनारायण पाटीदार, हाजी बाबू सलीम, डॉ पृथ्वी सिंह वर्मा,नाथूसिंह राठौर,पूर्व जिला पंचायत सदस्य मधु बंसल, ब्रजेश सक्सेना,श्याम सोनी, राजू गरासिया,ओम दीवान, ब्रजेश मित्तल, ओम शर्मा, मुकेश कालरा,चंद्रशेखर पालीवाल, भगत वर्मा, मनीष पोरवाल,मोहनसिंह जाट, मंगेश सेंघई, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र मोनू लोक्म, आरसागर कछावा, जोरन ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विनादसिंह भंवरासल, हिराद्यतुल्ला खान, सेवादास जिलाध्यक्ष गजेंद्र यादव,नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति, विमल शर्मा,नीमच ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष बलवंत पाटीदार, मनोहरसिंह अंब,रणजीतसिंह तंवर बबली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन मौजूद थे।

PRGI Reg. No. MPHIN/2023/90883

संपादक : ऐश्वर्य शर्मा

नीमच, बुधवार

27 अगस्त 2025

वर्ष - 03, अंक - 17 - मूल्य 02 रूपए

पृष्ठ - 04

E-mail: nmh.pawan@gmail.com

Contact: 9407423966, 8770664866

मध्यप्रदेश सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला...

फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदना होगा आसान

भोपाल। प्रदेश में गेहूं, धान, चना और उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी को और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब खरीदी केंद्रों की प्राथमिकता गोडाउन को दी जाएगी, जिससे खरीदे गए अनाज को ढोने में लगने वाला अतिरिक्त खर्च रोका जा सके।



यह घोषणा अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरुण शर्मा ने सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित स्टेट लेवल प्रोक्तोरमेंट रिफार्म कार्यशाला में की।

शमी के मुताबिक पिछले रबी सीजन में करीब 9 लाख किसानों से 77 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया। लगभग 20 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए। सरकार ने गेहूं खरीदी पर 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया। इसी तरह 6.50 लाख किसानों से 43.5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया।

उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसकी शुरुआत इंदौर से हो चुकी है। उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की जा रही है, जिससे अपात्र लोगों को बाहर किया गया है। लगभग 5.70 लाख नए उपभोक्ता जोड़े गए हैं।

आई.टी.आई. रामपुरा में केम्पस प्लेसमेंट ड्राईव कल

नीमच 26 अगस्त (निप्र)। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रामपुरा जिला नीमच में संस्था स्तर पर केम्पस प्लेसमेंट ड्राईव का आयोजन 28 अगस्त 2025 एवं 2 सितम्बर 2025 को किया जा रहा है। अधिकाधिक युवाओं से इस केम्पस प्लेसमेंट ड्राईव में उपस्थित होने का आग्रह प्राचार्य आईटीआई रामपुरा ने किया है। विस्तृत जानकारी आई.टी.आई.रामपुरा से प्राप्त की जा सकती है।

12th

सफर जोश का

के बाद

मंजिल कामयाबी की

MPPSC, SSC, BANK

रेलवे, पुलिस की तैयारी कीजिए

और डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, वाणिज्यिक कर अधिकारी, SP, DSP, CID इंस्पेक्टर, CBN इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमाण्डेंट, इक्वम टेक्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, बैंक क्लर्क, PO, मैनेजर आदि बनिये

सोनी कोचिंग क्लासेस

ISO 9001 : 2008 Certified

22 वर्षों का अनुभव।

1200 से अधिक छात्रों को नौकरी दिला चुके हैं।

धनीराम सगर मार्केट, गायत्री मंदिर के पास, भागेश्वर मंदिर रोड, नीमच मो. 9300905061

ज्ञानोदय

मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में

आयुष्मान

योजना लागू

5 लाख रूपए

प्रति वर्ष, पात्र परिवार को निःशुल्क उपचार

आयुष्मान भारत

अब बीमार नहीं रहेगा लाचार, अंचल के भव्य हॉस्पिटल में होगा निःशुल्क उपचार

अब उदयपुर एवं इंदौर जाने की जरूरत नहीं

सुपरस्पेशलिस्ट डॉक्टर्स

का समूह एक ही स्थान पर उपलब्ध

आयुष्मान कार्ड धारकों के निम्नलिखित बीमारियों कें उपचार निःशुल्क किए जाएंगें -

जनरल मेडिसीन

बाल चिकित्सा प्रबंधन

नवजात गहन शिशु इकाई

आपातकालीन चिकित्सा

जनरल सर्जरी

बर्न प्रबंधन

प्रसूति एवं स्त्री रोग

अस्थि एवं हड्डी रोग

गंभीर चोटें

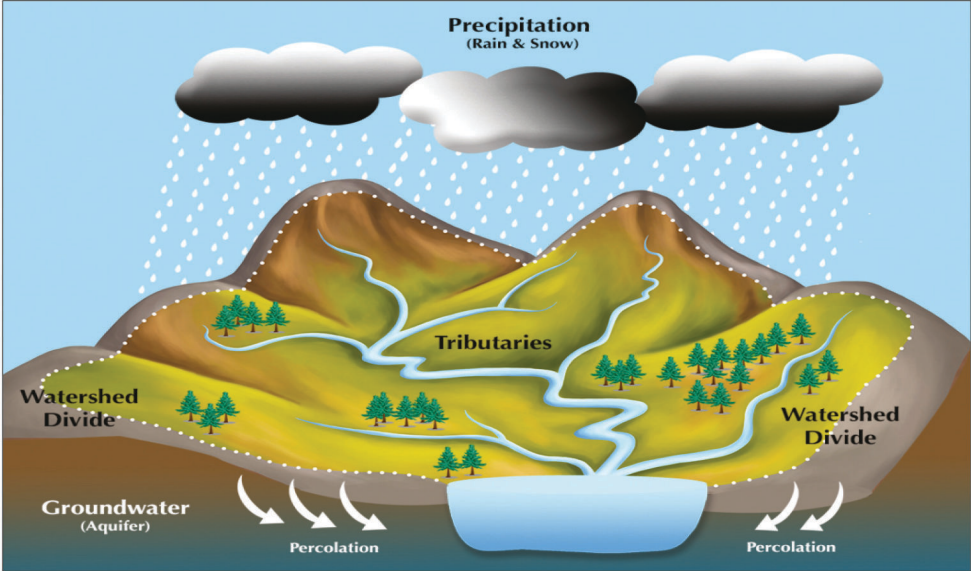
संक्रामक रोग

ज्ञानोदय मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

ज्ञानोदय महाविद्यालस के पीछे, कनावटी, नीमच ८6262778282



वॉटरशेड: साकार होता विकसित भारत का सपना



इससे बारिश का पानी बहकर बेकार नहीं जाता, बल्कि धीरे-धीरे धरती की प्यास बुझाता है, जिससे भूजल का स्तर बढ़ता है और मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है। इस योजना की सबसे बड़ी शक्ति इसकी जन-भागीदारी है। गाँव के लोग खुद बैठकर यह तय करते हैं कि तालाब कहाँ खोदना है, मेड़ कहाँ बनानी है और पेड़ कहाँ लगाने हैं। भूमिहीन परिवारों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी मुगीपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कामों से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस योजना के बहुत सुखद परिणाम मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे किसान भाई-बहनों को मिला है, जिनकी आमदनी में 8% से लेकर 70% तक की ठोस वृद्धि हुई है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि 2015 से अब तक, सरकार ने ₹.20,00,000 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च करके देशभर में 6,382 से अधिक परियोजनाएं चलाई हैं और लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने का काम किया है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ में, जहाँ कभी सूखा एक बड़ी समस्या थी, आज आदिवासी गाँवों में पानी भरपूर है और मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बढ़ गई है। परियोजना क्षेत्र के 22 गाँवों में भूजल स्तर एक मीटर तक बढ़ गया है। इससे खेती में भी परिवर्तन आया है। यहाँ के किसान भाई बताते हैं कि गाँव में चेकडैम बनने से अब वे मक्के के साथ-साथ

चने की फसल भी ले रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी ₹.50,000 से ₹.60,000 तक बढ़ गई है। साथ ही झाबुआ की ही परवलिया पंचायत में 12 खेतों में बने खेत तालाबों से किसानों की आमदनी ₹.1 लाख से ₹. 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर तक बढ़ी है। इस योजना के तहत 9 लाख से ज्यादा चेक डैम, रिसाव तालाब, खेत तालाब, जैसी वाटरशेड संरचनाएँ बनी हैं। 5.6 करोड़ से ज्यादा श्रम दिवस उपलब्ध हुए हैं, जिससे ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई है। वाटरशेड विकास परियोजनाओं के लागू होने से गाँवों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। जहाँ पहले पानी की कमी थी, उन परियोजना क्षेत्र में अब 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा नए इलाके में जल स्रोत फैले हैं, यानी 16% का इजाफा हुआ है। साथ ही अब किसान पारंपरिक फसलों के अलावा फलों और अन्य पेड़-पौधों की खेती भी करने लगे हैं, जिससे बागवानी और पेड़-पौधों की खेती का दायरा 12% बढ़कर 1.9 लाख हेक्टेयर पहुँच गया है।

राजस्थान के बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी इलाके में, जहाँ पानी की कमी किसानों को पलायन पर मजबूर कर रही थी, आज अनार की खेती से हरियाली लौट आई है। योजना के अंतर्गत 120 से अधिक किसानों को अनार के पौधे उपलब्ध कराए गए, जो वहाँ की बालू मिट्टी और सीमित पानी जैसी कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से पनप जाते

हैं। अनार की खेती ने न केवल आमदनी बढ़ाई, बल्कि बूढ़ीवाड़ा गाँव के मांगोलाल परांगी का कहना है कि उनके जैसे किसान अब अरंडी छोड़कर बागवानी की ओर बढ़ गए हैं। त्रिपुरा के दाशी रियांग और बिमन रियांग जैसे किसान योजना की मदद से अनानास की बागवानी करके अपनी बंजर भूमि को फिर से उपजाऊ बना रहे हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं।

इस पूरी क्रांति को जन-जन तक पहुँचाने और इसे एक जन-आंदोलन बनाने के लिए हमने 'वॉटरशेड यात्रा' भी निकाली। इस यात्रा के माध्यम से हमने देशभर में जल संरक्षण और भूमि संवर्धन के लिए एक जनजागरण अभियान चलाया। हमने इस योजना में तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया है। ह्यूबुवन जियोपोर्टल (सृष्टि) और ह्यूडिष्टि मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल उपकरणों से योजनाओं की प्रगति की सटीक निगरानी हो रही है। किसानों की मेहनत और हमारी योजनाओं की वजह से, देशभर के फसल क्षेत्र में बढ़ावती हुई है। सैटेलाइट से मिले आँकड़े बताते हैं कि फसल क्षेत्र में लगभग 10 लाख हेक्टेयर (5% की वृद्धि) और जल स्रोतों के क्षेत्र में 1.5 लाख हेक्टेयर (16%) की वृद्धि) का इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 8.4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बंजर जमीन अब फिर से खेती के योग्य बन चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज अमृतकाल में हम सब मिलकर भूमि संरक्षण की एक नई गाथा लिख रहे हैं। यह सिर्फ आँकड़े नहीं हैं, यह हमारे किसानों की मेहनत और उनके बेहतर भविष्य की जीती-जागती कहानी है। जब हम पानी और मिट्टी को बचाएंगे, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित कर पाएँगे। इस संकल्प को मिलकर पूरा करें और किसानों को समृद्ध तथा भारत को विकसित बनाएँ।

प्रधानमंत्री मोदी जी का मानना है कि केवल सरकार नहीं, समाज की भागीदारी से ही यह अभियान सफल होगा। उसी सोच के तहत ह्यूवॉटरशेड यात्राहू जैसी पहल से इस योजना को जन-जन तक पहुँचाया गया है और यह एक जनांदोलन बन चुका है। यह भारतीय किसानों की मेहनत और बदलते भविष्य की कहानी है। जब जल और मिट्टी सुरक्षित होंगी, तभी भारत सुरक्षित रहेगा। 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब गाँवों की धरती समृद्ध होगी और किसान खुशहाल होंगे। आइए, मिलकर जल और माटी के इस रूखा संकल्प को आगे बढ़ाएँ। (लेखक केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री है)

संपादकीय

फरियादी का हमला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को सुबह सविल लाईंस स्थित उनके कार्यालय पर आयोजित 'जनसुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति द्वारा हमले के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा कर जेड़ कैटेगरी कर दिया गया है। हमला गंभीर था, और जानलेवा भी हो सकता था। पुलिस ने यह कहा है। हमलावर गुजरात के राजकोट का रहने वाला सकरिया राजेश भाई खिम्बी भाई (41) बताया गया है, जिसे मौके पर ही दबोच लिया गया। उसे पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने हमले को 'मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश' का हिस्सा बताया है। पता चला है कि आरोपी पर पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं यानी वह आदतन अपराधी है, और कुछ कागजों में अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष पेश होने वाले फरियादियों की लाइन में जा लगा था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर किए गए इस हमले की पक्ष-विपक्ष सभी ने एक स्वर में कड़ी निंदा की है, और मांग की है कि इस मामले की कड़ाईसे जांच की जाए ताकि इस साजिश का खुलासा हो सके। बहरहाल, मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस घटना के अगले ही दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी नाथ के आवास के बाहर 'जनता दरबार' में पहुंचे एक फरियादी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। वह अपने क्षेत्र के विधायक के उत्पीड़न



की शिकायत लेकर पहुंचा था। इस प्रकार देखें तो इन दोनों मामलों में फरियादियों का असंतोष उभरा। एक में व्यक्ति ने खुद को मारना चाहता तो दूसरे मामले में आरोपी हत्या करने पर आमादा हो गया। दोनों मामलों में देखें तो हमलावर उपग्रंथी या असंतुष्ट गुट से फिलहाल तो संबंधित नहीं हैं। लेकिन उनमें असंतोष बेहद ज्यादा था। इसलिए जरूरी है कि सत्तारूढ़ सरकार अपने नागरिकों या असंतोष का खेलावा को तलाशने के भी प्रयास करें। कहीं सत्तारूढ़ विधायक के उत्पीड़न से ग्रस्त फरियादी 'बागी' होने तो तत्पर है, तो दूसरी तरफ 'न्याय' मिलने से निराश व्यक्ति मुख्यमंत्री पर ही हमला कर बैठता है। सत्ताधारियों को बेहद संजीदगी से उन हालात को साजगर बनाना चाहिए जो असंतोष के कारण बनते हैं, और पीड़ित विवेक खो बैठता है। बहरहाल, दोनों मामलों की अच्छे से पूछताछ करके न्यायोचित कार्रवाई किया जाना अभीष्ट है।

चितन-मनन

प्रेम और सहयोग का नाम है परिवार

पारिवारिक सदस्यों के त्याग, सहयोग, स्वच्छता, प्रेम, संतुष्टि व व्यसनमुक्ति से ही परिवार संयुक्त और समृद्धिशाली बनता है। वे सौभाग्यशाली हैं जो संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तथा जिन्हें माता-पिता का सान्निध्य प्राप्त हो रहा है। विश्व बंधुत्व की बात करने वालों को पहले अपने परिवार में बंधुत्व बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आज छोटी-छोटी बातों को लेकर परिवार टूट रहे हैं। हम अधिकारों की बजाए एक-दूसरे के हितों का ध्यान रखेंगे, तभी हमारे परिवार खुशहाल और सुदृढ़ होंगे।

एक माता-पिता अपने पाँच-पाँच बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करके योग्य बना देते हैं जबकि पाँच-पाँच बच्चे नानापां में अपने एक माता-पिता को संभालने से कतराते हैं। आज हम जितने बूढ़े दादा-दादी के प्रति लापरवाह हैं यदि हमारे बचपन में वे हमारे प्रति इतने ही लापरवाह होते तो हमारी क्या दुर्गति हो गई होती। इस बात को युवा पीढ़ी को अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए।

परिवार में ब्याह कर आई नई बहू को चाहिए कि जितने उम्र का पति उसे मिला है कम से कम उतने साल तो सास-ससुर का फर्ज मानकर उन्हें निभा देना चाहिए। इस पीढ़ी को व्यसनमुक्त होकर अपने माता-पिता की सेवा करने, उनके प्रणाम करने के तरीको को जीवन में अपनाना चाहिए। जीवन में सदाचार को अपना कर हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचार जीवन का प्रतिबिंब है। संतों की संगति से अच्छे विचार आते हैं। विचार अच्छे होना हमारी जागरूकता को दर्शाता है। हमारे विचार हमारे जीवन का परिचय देते हैं। रुपया-पैसे का लालच छोड़कर हमें जीवन में धार्मिक आराधना करते रहना चाहिए। जिससे हमारा जीवन और हमारे परिवार का जीवन सार्थक होगा।



नूपेन्द्र अभिषेक नूप

लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान उसकी संसद होती है। संसद वह संस्था है जहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्र की नीतियों, योजनाओं और कानूनों पर विचार-विमर्श करते हैं। यह वह सर्वोच्च मंच है जहाँ विभिन्न विचारधाराएं और दृष्टिकोण टकराते हैं और देशहित में समाधान निकलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भारतीय संसद की छवि हंगामे, तोड़फोड़, शोर-शराबे और गतिरोध का पर्याय बनती जा रही है। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र इसकी बानगी था, जो आरंभ से अंत तक त्रासद हंगामे की भेंट चढ़ गया। यह सत्र बेहद निराशा एवं अफसोसजनक रहा, क्योंकि सरकार और विपक्ष में टकराव उग्र से उग्रतर हुआ। राज्यसभा में केवल 41.15 घंटे और लोकसभा में 37 घंटे काम हुआ। संवाद एवं सौहार्द की कमी दिखी, कई सवाल अधूरे रहे, जिनका जवाब देश जानना चाहता था। यहाँ दोनों पक्षों से ज्यादा समझदारी, सौहार्द और संतुलित नजरिये की अपेक्षा थी, लेकिन देशहित के दोनो पक्षों ने नेस्तनाबूद किया। यह स्थिति केवल दुखद ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय भी है। लोकसभा के मानसून सत्र के लिए कुल 120 घंटे चर्चा के लिये निर्धारित थे, लेकिन कार्यवाही मात्र 37 घंटे ही चल पाई। यानी 70 प्रतिशत से अधिक समय लोकसभा में और 61 प्रतिशत से ज्यादा समय राज्यसभा में हंगामे और शोर-शराबे की भेंट चढ़ गया। संसद में बिताया गया प्रत्येक घंटा जनता के करोड़ों रुपये की कमाई से संचालित होता है। जब वही समय व्यर्थ हो जाए तो यह सीधे-सीधे जनता के साथ

अन्याय है। गुजरात के एक निर्दलीय सांसद ने यह प्रश्न उठाया भी कि जो सांसद हंगामा कर सदन को ठप कर देते हैं, क्या वे जनता के धन की बरबादी की भरपाई करेंगे? यह प्रश्न केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति हमारी गंभीरता की कसौटी भी है। काम कम, हंगामा अधिक-आखिर हमारे राजनीतिक दल एवं जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की मर्यादा एवं आदर्श को तार-तार करने पर क्यों तुले हैं? कैसी विडम्बना है कि लोकसभा की कार्यवाही के लिए 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे और इनमें से महज 55 का मौखिक उत्तर मिल सका। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है और आवश्यक भी। विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, सत्ता को जवाबदेह बनाना। लेकिन यह काम हंगामे, नारेबाजी और सदन की कार्यवाही बाधित करने से नहीं हो सकता। संसद संवाद का मंच है, न कि संघर्ष का अखाड़ा। दुर्भाग्य यह है कि आज बहस और तर्क की जगह हंगामे और टकराव ने ले ली है। इससे न तो जनता की समस्याओं पर गंभीर विमर्श हो पाता है और न ही संसद की गरिमा सुरक्षित रह पाती है। सत्र शुरू होने के पहले कार्य मंत्रणा समिति में सरकार और विपक्ष के बीच कुछ मुद्दों पर चर्चा की सहमति बनी थी। लेकिन, सत्र शुरू होने के साथ ही उसे भुला दिया गया। संसदीय परंपरा में विरोध भी अधिकार है, लेकिन इसकी संवेदन से सदन की गरिमा और उसके कामकाज पर असर पड़ना दुर्भाग्यपूर्ण एवं चिन्ताजनक है। भारत का हर नागरिक संसद से अपेक्षा करता है कि वहां उसकी समस्याओं पर चर्चा होगी-बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दे प्राथमिकता पाएंगे। लेकिन जब टीवी स्क्रीन पर वह अपने प्रतिनिधियों को मेज थपथपाते, नारे लगाते और वेल में जाकर हंगामा करते देखता है तो उसका विश्वास टूटता है और मन आहत होता है। उसे लगता है कि जिन नेताओं को उसने वोट देकर भेजा था, वे उसके हितों की बजाय केवल राजनीति का खेल खेल रहे हैं। यही कारण है कि आज लोकतंत्र के प्रति आम नागरिक का मोहभंग बढ़ रहा है। वैसे भी यह मानसून सत्र ऐसे वक्त हो रहा था, जब भारत नई चुनौतियों से गुजर रहा है। विदेश

और आर्थिक, दोनों मोर्चों पर हालात तेजी से कवरट ले रहे हैं। ऐसे में और भी अहम हो जाता है कि संसद में इस पर सार्थक चर्चा होती और वाद-विवाद से रास्ता निकाला जाता। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन-एसआईआर और ऑपरेशन सिंदूर पर कई सवाल बचे रह गए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के सजा की स्थिति-यानी जेल में होने पर पद से हटाने वाले संविधान संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस गंभीरता की जरूरत थी, वह नहीं दिखी। संसद में हंगामे की प्रवृत्ति में केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष भी अक्सर इसमें बराबर का भागीदार होता है। जब कोई दल विपक्ष में होता है तो वह विरोध के लिए हरसंभव कदम उठाता है, और जब वही दल सत्ता में आता है तो संसद की गरिमा की दुहाई देने लगता है। यह दोहरा रवैया लोकतंत्र को कमजोर करता है। संसद को सुचारुरूप से चलाना केवल सरकार की ही नहीं, बल्कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। दोनों पक्षों को यह समझना होगा कि वे जनता के सेवक हैं, और जनता उनके कामकाज पर पैनी नजर रखती है। संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने के लिए कठोर नियमों की आवश्यकता है। यदि कोई सांसद बार-बार हंगामा करता है, सदन की कार्यवाही बाधित करता है, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आर्थिक दंड एक प्रभावी उपाय हो सकता है। जिस प्रकार एक कर्मचारी को कार्यालय में अनुशासन भंग करने पर वेतन काटा जाता है, उसी प्रकार सांसद का भत्ता और सुविधाएं भी रोकी जानी चाहिए। तभी उन्हें यह समझ आएगा कि संसद खेल का मैदान नहीं बल्कि देशहित का पवित्र मंच है। कई बार सांसद यह तर्क देते हैं कि यदि उनकी आवाज संसद में नहीं सुनी जाती तो वे मजबूर होकर हंगामा करते हैं। लेकिन यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। संसद में बोलने के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, विशेष उल्लेख, स्थायी समितियाँ-ये सभी मंच संसदों को मुद्दे उठाने का अवसर देते हैं। यदि इन मंचों का सही उपयोग हो तो हंगामे की जगह आवश्यकता नहीं रहती। सड़क की राजनीति और संसद की राजनीति में अंतर होना चाहिए। यदि संसद

भारत और चीन: क्या गुल खिलाएगा संवाद

रहा है कि रिशतों में नई गरमाहट लौट रही है। परंतु इस गरमाहट के साथझुसाथ सतर्कता और विवेक भी उतना ही आवश्यक है। भारतझुचीन संबंधों की नींव 1950 के दशक में 'हिन्दी-चीनी भाई-भाई' के नारे के साथ रखी गई थी। परंतु 1962 का युद्ध दोनों देशों के रिशतों में निर्णायक मोड़ लेकर आया। सीमा विवाद, विशेषकर अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर असहमति, आज भी दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद का कारण है। उसके बाद से समय-समय पर रिशतों में उतार-चढ़ाव आते रहे। 2017 का डोकलाम संकट और 2020 का गलवान संघर्ष इस अविश्वास की पराकाष्ठा थे। दोनों घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा विवाद अब भी संबंधों का सबसे बड़ा अवरोधक है।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 3,488 किमी. लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा से जुड़ा है। कई दैर की वाताओं और सैन्य समझौतों के बावजूद समाधान अब तक संभव नहीं हो पाया है। हाल ही में हुई वाताओं में सहमति बनी है कि सीमा विवाद को अलग रखते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह 'टू टैक मुवमेंट' (दोहरी रणनीति) है, जिसमें सीमा विवाद और द्विपक्षीय संबंध समानांतर रूप से चलेंगे। भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंध बेहद जटिल हैं। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार

लगभग 136 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। लेकिन इसमें असंतुलन स्पष्ट है। भारत जहां चीन से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक सामान, माशीनरी, रसायन और दवाओं का कच्चा माल आयात करता है, वहीं उसका निर्यात अपेक्षाकृत बहुत कम है। इस कारण व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की चिंता यह भी है कि चीन का प्रभुत्व व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह भारत के बाजार पर हावी होकर आत्मनिर्भरता और 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं को चुनौती देता है। हालांकि, भारतीय आईटी, फार्मा और कृषि क्षेत्र में चीन की बढ़ती मांग भारत के लिए अवसर भी प्रस्तुत करती है। सवाल है कि भारत इस असंतुलन को कैसे कम करेगा और आर्थिक संबंधों को संतुलित एवं परस्पर लाभकारी कैसे बनाएगा।

भारत-चीन संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा और सामरिक हितों से जुड़ा हुआ है। चीन पाकिस्तान के साथ मिल कर 'स्ट्रिंग ऑफ पल्स' रणनीति के तहत हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत की घेराबंदी कर रहा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता के लिए गंभीर चुनौती है क्योंकि इसका मार्ग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन की नौसैनिक गतिविधियां भी हिन्द महासागर और दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा चिंताओं को जगह करती हैं। यही कारण है कि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल कर क्वाड समूह को



मजबूत कर रहा है। भारतझुचीन संबंध द्विपक्षीय दायरे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वैश्विक सामरिक संतुलन से भी गहराई से जुड़े हैं। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई मुलाकातें, चाहे 2019 का महाबलीपुरम शिखर सम्मेलन हो या हाल में वांग यी की यात्रा, दर्शाती हैं कि संवाद ही आगे का रास्ता है। दोनों देशों ने तय किया है कि सीमा प्रबंधन के तंत्र को मजबूत किया जाए और सैनिक तनाव को कम करने के लिए नियमित वार्ता और हॉटलाइन का इस्तेमाल किया जाए। पर्यटन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाए। 'पीपुल-टू-पीपुल कॉन्टेक्ट' दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का प्रभावी साधन हो सकता है।



अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजना और उसके सुनहरे भविष्य की कामना करना हर माता-पिता का हक होता है। अपने बच्चे के जन्म से ही वह उसके भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। प्री-स्कूलिंग, कॉलेज सब तय हो गया होता है, लेकिन विशेषज्ञों का दावा किसी और ही तरफ इशारा करता है। उनके अनुसार कम उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गलत असर डालता है।



मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है, कम उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना

बच्चों को प्री-स्कूलिंग के लिए भेजना हर पेरेंट्स के लिए काफी बड़ा कार्य होता है। यह पहली बार होता है उनका नन्हा-सा बच्चा अपने जीवन को सुधारने और उससे नई चीजों को सीखने के लिए वास्तविक दुनिया में कदम रखता है। स्कूलिंग के दौरान मिलने वाली औपचारिक शिक्षा उसे उसके सुनहरे भविष्य के लिए तैयार करती है। हम में से अधिकांश लोगों का मानना है कि यदि आपका बच्चा इसके लिए तैयार है, तो उसे प्री-स्कूल में एडमिशन दिलाने का कोई सही या गलत समय नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ वास्तव में इससे सहमत नहीं हैं। एक अध्ययन के अनुसार, भले ही आपका बच्चा प्रतिभाशाली हो और उसमें जल्दी सीखने की कौशलता हो, फिर भी उन्हें बहुत जल्दी स्कूल भेजना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। रिसर्चरों का कहना है कि आपका अपने बच्चों को प्री-स्कूल जल्दी भेजने का आग्रह स्वाभिक है, लेकिन अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही समय का इंतजार करना ही बेहतर होगा।

बच्चों को जल्दी स्कूल भेजना इसलिए होता है हानिकारक नए अध्ययन के शोधकर्ता सलाह देते हैं कि माता-पिता किडरगार्टन में अपने साथियों के साथ अपने बच्चों की उम्र पर विचार करें। एक बड़ा अंतर आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। एक नए अध्ययन के अनुसार, जो बच्चे अपने साथियों से छोटे होते हैं (स्कूल शुरू करने के लिए न्यूनतम आयु कट-ऑफ के करीब), वह कक्षा में खराब प्रदर्शन करते हैं और उन्हें साथियों की तुलना में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन से पता चला है कि बहुत जल्दी स्कूल शुरू करना आपके बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।



स्टडी क्या कहती है

अध्ययन के लिए, शोधकर्ताओं की टीम ने एक मौजूदा अध्ययन से एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किया, जिसे "स्कूल अध्ययन में सहायक शिक्षक और बच्चे" कहा जाता है। यह अध्ययन डेवीन, इंग्लैंड के 80 विभिन्न स्कूलों के 2,075 प्राथमिक विद्यालय के पांच से नौ वर्षों के छात्रों पर किया गया था। अध्ययन में माता-पिता और शिक्षकों से पूछे गए सवालों की एक श्रृंखला शामिल थी, जिससे यह पता चला कि जल्दी स्कूल भेजने से बच्चों में चिंता और भय, अपने साथियों के साथ खराब संबंध, व्यवहार और एकाग्रता के मुद्दों जैसी नकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं।

बच्चे का वेट बढ़ने में पैरेंट्स का होता है इंपॉर्टेंट रोल

अक्सर ही खुद और बच्चे के वेट को लेकर टेंशन हो जाती है कि लगातार वजन कैसे बढ़ता ही जा रहा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चे के वेट बढ़ने में पैरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। हाल ही में इसपर एक स्टडी भी सामने आई। आइए जानते हैं।

अक्सर ही यह देखा गया है कि परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है तो दूसरों का भी वजन बढ़ता ही जाता है। हालांकि अधिकतर यह पैरेंट्स और बच्चों में देखने को मिलता है। यानी कि जिन पैरेंट्स का वेट ज्यादा होता है उनके बच्चों का भी वजन बढ़ता ही जाता है। वहीं पैरेंट्स इस बात को लेकर खासे परेशान नजर आते हैं कि कैसे बच्चे का वजन कम हो। हाल ही में ऐसे मामलों पर की गई स्टडी से यह बात सामने आई है कि कैसे अपनी लाइफस्टाइल में कुछ तब्दीलियां लाकर पैरेंट्स अपने साथ ही बच्चों के वेट बढ़ने पर नियंत्रण कर सकते हैं। स्टडी के मुताबिक पैरेंट्स बच्चों को जो भी खिलाते हैं बच्चे वह खाते जाते हैं। इससे उनका वजन बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी खाने और अच्छी आदतों के अनुसार ढालते हैं तो वह वजन बढ़ने की समस्या से निजात पा सकता है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए (डिवलैपिंग रिलेशनशिप्स डैट इन्क्लूड वैल्यूज ऑफ इंटिंग ऐंड एक्सर्साइज) रिसर्च किया। यानी कि खाने और एक्सर्साइज के जरिए बच्चों और उनके पैरेंट्स को बढ़े हुए वजन को नियंत्रित या कम करने के लिए प्रेरित किया। इस बारे में अमेरिका के लूसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स कैली हॉकिन्स और कॉर्बी के मार्टिन कहते हैं कि बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव उनके माता-पिता का ही पड़ता है।

रिसर्च में 16 परिवारों पर हुई स्टडी

पैरेंट्स और उनके बच्चों के बढ़ते वजन को कैसे नियंत्रित और कम किया जा सके इसके लिए 16 परिवारों को 19 सप्ताह तक ऑब्जर्व किया गया। हालांकि इस दौरान उन्हें अपनी और बच्चों की लाइफस्टाइल में शामिल करने की बात कही गई थी। इसके बाद स्टडी में 2 से 6 साल के बच्चों का बीएमआई (बॉडी मास इंडेक्स) 75 प्रतिशत से अधिक पाया गया। बता दें कि (डिवलैपिंग रिलेशनशिप्स डैट इन्क्लूड वैल्यूज ऑफ इंटिंग ऐंड एक्सर्साइज) के सेशन में यह बात सामने आई कि इसमें नियमित नैक और खाने के साथ ही फिजिकल एक्टिविटीज के होने से बच्चों के बीएमआई में कमी देखी गई। साथ ही उनका वजन भी नियंत्रित था। वहीं पैरेंट्स के वजन में भी थोड़ी तब्दीलियां देखने को मिली। लेकिन जिन बच्चों को ड्राइव के सेशन में शामिल नहीं किया गया केवल जानकारी ही दी गई थी उनके वजन में वृद्धि दर्ज की गई। शोधकर्ताओं के मुताबिक संयमित, नियमित खानपान और एक्सर्साइज से खुद और बच्चे दोनों के ही वजन को नियंत्रित किया जा सकता है।



परिणाम क्या निकला

अध्ययन के अंत में, यह निष्कर्ष निकाला गया कि छोटे बच्चों में उनके साथियों की तुलना में खराब मानसिक स्वास्थ्य होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि कम उम्र में बड़े साथियों के साथ रहना थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। समस्या उन बच्चों में विशेष रूप से प्रमुख थी जो नई चीजें सिखने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और समय से पहले पैदा हुए थे। यह खोज माता-पिता को इस बारे में विचार करने में मदद कर सकती है कि औपचारिक शिक्षा सेटिंग में बच्चे का नामांकन कब करना है, ताकि उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ भी हानिकारक सिद्ध नहीं हो।

एडमिशन की सही उम्र

ज्यादातर लोगों का मानना है कि जितनी जल्दी वह अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा शुरू करने के लिए 3 साल एक आदर्श उम्र है। हालांकि, अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए।

- उन्हें शौचालय प्रशिक्षित होना चाहिए।
- वह थोड़े समय के लिए स्थिर बैठ सकते हैं।
- वह अपने माता-पिता से दूर आराम से समय बिता सकते हैं।
- वह अपनी जरूरतों को बता सकते हैं और दूसरों की बातें सुन सकते हैं।

बालों से डैंड्रफ दूर करने के लिए लगाएं टमाटर का जूस

टमाटर प्रकृति का दिया एक ऐसा उपहार है जो एंटीऑक्सीडेंट्स और विटमिन से भरपूर है। टमाटर खाना सेहत ले लिए लाभदायक है और इसे चेहरे पर लगाने से स्किन हेल्दी बनती है। इतना ही नहीं अगर आप इसे अपने बालों पर लगाएंगे तो रुखे और बेजान बाल चमकदार और रेशमी हो जाएंगे। आइए, यहां जानते हैं कि टमाटर का जूस बालों पर लगाने से क्या-क्या फायदे होते हैं।

- टमाटर का जूस बालों पर लगाने से बालों का टेक्चर स्मूद होता है और बालों की शाइनिंग में बढ़ती है।
- टमाटर का जूस बालों में पीएच लेवल बैलेंस करता है, जिससे रुखे और बेजान बालों में वॉल्यूम आ जाता है।
- टमाटर में बड़ी मात्रा में विटमिन ए और विटमिन सी होता है। इसके जूस को बालों पर लगाने से बालों की स्कल्प को मजबूती मिलती है।
- टमाटर का जूस लगाने से बालों में मजबूती आती है और बाल जल्दी से दोमुड़े नहीं होते हैं। साथ ही ग्रोथ अच्छी बनी रहती है।

ऐसे बनाएं कंप्लीट पैक

अगर आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गई है और डैंड्रफ से भी परेशान हैं तो टमाटर के जूस में शहद मिलाकर हेयर मास्क बनाकर बालों पर लगाएं। आधा घंटा लगाए रखने के बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें। हो सकता है लगाने के तुरंत बाद आपको फिर भी हल्की जलन महसूस हो या खुजली हो लेकिन आप परेशान न हों। ऐसा टमाटर में एसिडिक प्रॉपर्टी होने के कारण होता है।



आपके किचन में मौजूद है सन टैन हटाने के आसान नुस्खे

अगर आप भी बीच पर छुट्टियां बिताकर हॉलिडे की यादों के साथ-साथ सन टैन लेकर लौटी हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। गर्मियों में कितना भी धूप से बचो, सन टैन हो ही जाता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं सन टैन रिमूवल के कुछ तरीके, जिन्हें आप घर पर ही आजमा सकती हैं। खास बात ये कि ये चीजें आपके किचन में ही मिल जाएंगी।

खीरे की फ्रेश स्लाइस



खीरे की फ्रेश स्लाइस लें। इसे फेस के साथ-साथ सन टैन प्रभावित क्षेत्रों पर हल्के हाथों से रगड़ें। लगाने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और फिर पानी से धो लें। टैनिंग दूर हो जाएगी।

हल्दी, बेसन और दही का पैक

दो चम्मच बेसन, दो चम्मच हल्दी पाउडर और दो



चम्मच दही लें और इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाकर लें। अब इस मिश्रण को अपने फेस और सन टैन प्रभावित बॉडी पार्ट्स पर लगाएं। तब तक लगा रहने दें, जब तक वह पूरी तरह से सूख न जाए। जब सूख जाए, तो पानी से धो लें।

शहद और नींबू का पैक

दो चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू का रस लें। इसे मिलाकर तब तक रगड़ें 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। अब पानी से धो लें। टैनिंग दूर करने का यह सबसे आसान तरीका है।

कच्चा दूध

थोड़ा सा कॉटन लें लें और बिना उबले हुए कच्चे दूध में कॉटन को भिगोएं और इसे फेस पर लगाएं। इसे 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। फिर चेहरे को पानी से धो लें।



घर में छोटे बच्चे हैं तो परफ्यूम और डियोड्रेंट यूज करते वक्त बरतें सावधानी

बॉटल पर लिखे निर्देशों का पालन न करने से नुकसान हालांकि इन परफ्यूम्स और डियोड्रेंट्स का इस्तेमाल करते वक्त जिस एक चीज का हम सब ध्यान नहीं रखते वह है बॉटल पर लिखे निर्देशों का पालन करना जो कई बार हानिकारक साबित हो सकता है। हाल ही में हुई एक स्टडी में यह बात साबित भी हो चुकी है कि बच्चों को लगने वाली चोट में 12.7 प्रतिशत चोटें पर्सनल केयर प्रॉडक्ट्स की वजह से लगती हैं जिनमें खुशबू और सुगंध से जुड़ी परफ्यूम और डियोड्रेंट जैसी चीजें शामिल हैं। इस तरह की चीजें बच्चों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं इसलिए इनका इस्तेमाल करते वक्त माता-पिता को भी काफी सावधानी बरतनी चाहिए।

इन चीजों को छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें

परफ्यूम और डियोड्रेंट जैसी चीजों को बच्चों की पहुंच से बहुत दूर रखें क्योंकि अगर बच्चे गलती से भी इन्हें अपनी आंख, नाक, कान या मुंह में स्प्रे कर लें तो यह

बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इतना ही नहीं अगर घर में बहुत ज्यादा छोटे बच्चे हैं तब भी पैरेंट्स को बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए वरना बच्चों द्वारा इन चीजों की बॉटल, ढक्कन आदि चीजों को मुंह में लेने की वजह से चोकिंग का भी खतरा रहता है।

बच्चे अगर यूज करें तो सेहत से जुड़ी समस्याओं का खतरा

अगर आपके घर में 13 से 17 साल के बीच के किशोर हैं तो उनमें संगी-साथियों के प्रेशर की वजह से समस्याएं अलग होती हैं। बड़े बच्चे खुद भी अच्छा स्मेल करने के लिए इन प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऐसे में छोटी उम्र में परफ्यूम या डियोड्रेंट का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों में फिजिकल हेल्थ से जुड़ी कई तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं। साथ ही बच्चे बॉटल पर लिखे निर्देश पढ़े बिना इसे सीधे स्किन पर स्प्रे कर लेते हैं जिससे उन्हें स्किन एलर्जी, रिएक्शन, अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत जैसी कई समस्याएं भी हो सकती हैं।

उद्योगों के विकास से होगा 'विकसित भारत' का सपना साकार : सीएम मोहन यादव

भोपाल। एमपी के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि उद्योगों के हित में ही राष्ट्र का हित निहित है। लघु और कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सीमित संसाधनों का समुचित उपयोग कर हम इन उद्योगों के विकास की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्वतंत्रता के अमृत काल में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण हमारे उत्कर्ष को दर्शाता है। उद्योगों के विकास के लिए हमें पूरे देश के परिदृश्य में सौचना होगा। सभी जगह समान रूप से उद्योग लगाने होंगे, तभी संतुलित विकास हो सकेगा। देश हित में हम सब मिलजुलकर काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि हम उद्योगों को विस्तार देने के लिए उद्योगपतियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमने समाज के सभी वर्गों का बराबर ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को लघु उद्योग भारती के गोविंदपुरा औद्योगिक प्रक्षेत्र में नवनिर्मित प्रदेश कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लघु उद्योग भारती के करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित प्रदेश कार्यालय भवन 'उद्यम सेतु' का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर लोकार्पण किया।

लोकार्पण अवसर पर लघु उद्योग भारती का द्वि-वार्षिक प्रादेशिक सम्मेलन और स्टार्टअप एवं लघु उद्यमी महाकुंभ-2025 भी आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य अतिथियों के साथ लघु उद्योग भारती के नए ब्रोशर का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने घोषणा की कि किसी भी प्रकार का संस्थागत या बैंक लोन चुकता होते ही संबंधित बंधक संपत्ति मॉर्टगेज या डबल मॉर्टगेज से मुक्त हो जाएगी। इस प्रावधान का लाभ हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों (एमएसएमई इंडस्ट्री) को भी देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना और इससे जुड़ी सभी कठिनाइयों का समुचित हल भी निकाला जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम एमएसएमई उद्योगों की स्थापना से जुड़ी सभी प्रकार की अनुमतियां को समयबद्ध



कार्य योजना की अनुरूप समय-सीमा में देने का प्रावधान करने जा रहे हैं। प्रदेश में रोजगार आधारित उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रदेश में नया आईटीआई पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए भी नीति से प्रावधान अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रदेश

में रिसर्च वर्क को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं। आईआईटी इंदौर में शोध कार्यों के लिए देशी और विदेशी शिक्षण संस्थानों के स्टडी सेंटर के लिए हमारी चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लघु उद्योगों के साथ हमेशा साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करना होगा। इसी से

ये रोजगार के सबसे बड़े निर्माता हैं। एमएसएमई वह पुल है, जो मेहनतकश हाथों को बड़े बाजारों से जोड़ता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज भारत में 6 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हैं, जो देश की जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत से अधिक योगदान देते हैं और कुल

निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। आज हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाए हैं, तो इसमें एक बड़ा योगदान लघु उद्योगों का ही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' का आख्यान हमें बताता है कि आत्मनिर्भर भारत का मार्ग बड़े-बड़े उद्योगों से नहीं, बल्कि घर-घर की चौखट से चलने वाले छोटे उद्योगों से ही निकलता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटरप्राइजेज को मैक्सिमम सपोर्ट देने की बात कही है, जिससे ये सभी उद्योग मैक्सिमम ग्रोथ हासिल कर सकें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लघु उद्योग भारती से जुड़े लघु उद्योगपति केवल मुनाफे के लिए काम नहीं करते, गौव, परंपरा और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। आप हर छोटे उद्यमी की आवाज बन रहे हैं। आप संगठन में शक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु उद्योगपति 'दाम कम, दम ज्यादा' मंत्र के साथ अपनी विश्वसनीयता बनाएँ, एक बार जो आपका प्रोडक्ट खरीदे, वो बार-बार खरीदे। तकनीकी से जुड़ें, मार्केटिंग सीखें, ऑनलाइन बाजार से जुड़ें। अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स बेवसाइट से जोड़कर लोकल से ग्लोबल बनाएं। कौशल भारत अभियान और नई शिक्षा नीति इस दिशा में बड़ा कदम है। छोटे उद्योगों के केंद्र में हमारी मातृशक्ति है। लाइली बहनों की भागीदारी से न सिर्फ परिवार की आमदनी बढ़ती है, साथ ही समाज में आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण का मार्ग भी खुलता है। लघु उद्योग ही स्वदेशी का आधार हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष

2047 में जब भारत विकसित और आत्मनिर्भर होगा, उसमें लघु उद्योगों की भूमिका सबसे बड़ी होगी।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि लघु उद्योग की सुरक्षा जरूरी है। यह लोगों को रोजगार देते हैं। यह घरों को आबाद बनाए रखते हैं। इनसे समाज के कमजोर वर्ग के लोग रोजगार पाते हैं। यह लघु उद्योग ही देश को चलाते हैं। इस मायने में लघु उद्योग हमारे देश की सामाजिक संरचना के संरक्षक भी हैं। बड़े उद्योगों के सामने बने रहना इनके लिए एक बड़ी चुनौती होती जा रही है। डॉ. कृष्ण गोपाल ने कहा कि लघु उद्योग सिर्फ भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में संकट में हैं। परंतु भारत में फिर भी ये उद्योग जीवित हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम भारतीय अपनी परंपराओं, अपने मूल्यों और अपने लोगों से अंतर्मन से जुड़े हुए हैं। हमें एक बार फिर स्वदेशी भाव से जोड़ना होगा। लघु उद्योगों से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि यह कार्बन उत्सर्जन नहीं करते। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूर और कारीगरों का सम्मान होना चाहिए। हम सभी को देश के उद्योग कानून और नियमों का पालन करना चाहिए। कर का अपवचन नहीं करना चाहिए, क्योंकि करों से ही देश की बुनियाद तैयार होती है, विकास होता है। उन्होंने बताया कि लघु उद्योग भारती द्वारा प्रदेश के पांच आईटीआई को मॉडल आईटीआई के रूप में डेवलप कर दिया गया है। कार्यक्रम को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री तथा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप, लघु भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, लघु उद्योग भारती के प्रांताध्यक्ष राजेश मिश्रा एवं अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।

जमीन हड़पने की नीयत से 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान को पड़ोसी द्वारा किया जा रहा प्रताड़ित

अधिकारियों पर भी लगाए झूठे आरोप, पीड़ित ने कलेक्टर से लगाई गुहार

नीमच। नीमच के मनासा तहसील के ग्राम पड़दा में 75 वर्षीय निर्धन बुजुर्ग अनुसूचित जाति किसान कचरूलाल खटीक ने कलेक्टर जनसुनवाई में अपनी पीड़ा रखते हुए गांव के ही महेश पिता नाथुलाल मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने कहा कि विपक्षी महेश, उनकी कृषि भूमि पर जबरन कब्जा जमाने की नीयत से लगातार उत्पीड़न कर रहा है, झुठी शिकायतें कर प्रशासन को गुमराह करता है और अधिकारियों पर दबाव बनाता है। कचरूलाल ने जनसुनवाई में प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेख किया कि उनकी तथा उनकी पत्नी मांगीबाई के नाम से मौजा पड़दा में क्रमशः सर्वे नंबर 86/1/4 रकबा 0.3640 हेक्टेयर एवं 86/1/7 रकबा 0.4450 हेक्टेयर कृषि भूमि है। ये भूमि शासन से लगभग 30-35 वर्ष पूर्व पट्टे पर मिली थी और तभी से वे स्वयं इस पर खेती कर जीवनयापन कर रहे हैं। प्राथी की भूमि उत्तर दिशा में मातारंडी जाने वाले मार्ग से लगी हुई है, जिसके बाद विपक्षी की भूमि आती है।पीड़ित ने आरोप लगाया कि विपक्षी महेश मेघवाल अकारण इर्था रखता है और बार-बार दबाव बनाता है कि भूमि उसे



अधबटाई पर दी जाए। जब बुजुर्ग किसान ने उसकी बात नहीं मानी तो वह आए दिन झगड़ा करता है। दिनांक 22 अगस्त 2025 को सुबह 10 बजे जब कचरूलाल अपनी कृषि भूमि पर मौजूद थे, तब विपक्षी महेश ने अचानक आकर मां-बहन की अश्लील गालियां दीं और जातिभूचक शब्दों से अपमानित करते हुए धमकी दी कि "तुम्हारा खेती करने से कोई वास्ता नहीं, मैं तुमसे यह जमीन छुड़वा दूंगा।" इस घटना से वृद्ध किसान भयभीत है।

पीड़ित की पोती दुर्गाबाई ने भी कलेक्टर को अवगत कराया कि विपक्षी महेश मेघवाल बार-बार झुठी शिकायतें करता है, यहां तक कि अधिकारियों के खिलाफ भी गलत आरोप लगाकर उन्हें भ्रमित

करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य कचरूलाल की जमीन पर कब्जा करना है और एससी-एसटी कानून का दुरुपयोग कर दबाव बनाने की

कोशिश करता है। बुजुर्ग किसान कचरूलाल ने प्रशासन से निवेदन किया कि उसकी वृद्धावस्था और निर्धनता का फायदा उठाकर की जा रही प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए और विपक्षी महेश मेघवाल के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि उपरोक्त शिकायतों के बाद मनासा तहसीलदार द्वारा पीड़ित की जमीन का बताकन भी किया गया है और कुछ हिस्से पर अतिक्रमण पाया गया था उसे पीड़ित ने खुद ही हटा दिया है। और इस मामले में सीमांकन के आदेश भी हो चुके हैं।

कलेक्टर चंद्रा ने की जनसुनवाई,75 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नीमच 26 अगस्त (निप्र)। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जनसुनवाई करते हुए 75 आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित जिला अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, बी.एस.कलेश, सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में गोटडा के मदनलाल, भगवानपुरा के अजय कुमार, गिरदीड़ा के भरत, नई ननौर की वजीबाई, श्रीपुरा रामपुरा के देवीलाल, नीमच सिटी की निर्मलाबाई, धनरियाकलां के रमेशचंद्र, चडौली के जगदीश, खजूरिया के रामचंद्र, मनासा की पायल, सुवाखेड़ा के कमलेश, नीमच सिटी की गुड्डिबाई,

भायेश्वर मंदिर रोड नीमच के गोपालचंद्र, एकता कालोनी नीमच की दुलीसबाई, अठाना के अकबर ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इसी तरह थडौली के पारस, पिपल्यारावजी की जमुना, नीमच सिटी के राहुल माली, मोड़ी के कारूलाल, कुचडौद की चंदाबाई, जावद की मुन्डीदेवी, लक्कड़ मण्डी नीमच के राजीव, पिपलिया नाथावत के लक्ष्मणसिंह, धामनिया के अशोक कुमार, थडौद के नाथूनाथ ने भी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किए, जिस पर कलेक्टर चंद्रा ने प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

आयुष्मान कार्ड पाकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर रहे बुजुर्ग- श्री परिहार

प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित,4 का पीपीपी मॉड पर संचालन हेतु एमओयू हस्ताक्षरित

नीमच । आयुष्मान कार्ड एवं निःशुल्क उपचार पाकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे है बुजुर्ग, यह बात सोमवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश स्तरीय वर्चुअली कार्यक्रम में विधायक श्री दिलीपसिंह परिहार ने कही। जबलपुर के मुख्य समारोह से मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ला, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने प्रदेश के साथ ही जिले को विभिन्न सीगानों दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने कहा , कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर विस्तार किया जा रहा है इसी कड़ी में चरणबद्ध एवं योजनाबद्ध मध्य तरीके से प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में श्योपुर एवं सिंगरौली के मेडिकल कॉलेज को लोकार्पित किया गया है तथा धार ,कटनी, पन्ना, बैतुल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित



नवीन मेडिकल कालेज खोले जाने हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये हैं।

इस अवसर पर अतिथियों ने आयुष्मान भारत अंतर्गत हितग्राहीयों के लिये व्हाट्सअप चैट बोर्ड ''आयुष्मान सखी'' का शुभारंभ भी किया। चैट बोर्ड के नम्बर 0755-2762582 पर कोई भी हितग्राही आयुष्मान

योजना की जानकारी, पात्रता की जाचें, आयुष्मान वालेटी की जानकारी, संबद्ध अस्पतालों की सूची , आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने की सुविधाओं के साथ ही अन्य सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे।

कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विधायक श्री दिलीप सिंह परिहार ने कहा, कि जिला चिकित्सालय

में निरंतर स्वास्थ्य सुविधओं का विकास एवं विस्तार हो रहा है। गरीबों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में विधायक श्री परिहार ने हितग्राही कमला देवी शर्मा ,शमीम बानो, मंगलकुमार गोराना, ललित बाई को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। कार्यक्रम को जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव ने

संबोधित करते हुए कहा कि जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत 70 प्लस से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन , श्रमिक कार्ड पात्रता एवं धरती आबा जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान के तहत भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। श्री वैष्णव ने जिले में आयुष्मान कार्ड के शेष हितग्राहियों के कार्ड शीघ्र बनाने के निर्देश दिए ।

इस अवसर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा.आर. के.खद्योत, श्री विरेन्द्रकुमार सखलेचा मेडिकल कालेज के डीन डा.आदित्य बोरड, सिविल सर्जन डॉ.महेंद्र पाटील, आयुष्मान भारत के नोडल अधिकारी डॉ.भेरूलाल सिसोदिया, डा.संगीता भारती, डा.मनीष यादव, सर्वश्री मोहन सिंह राणावत, दारासिंह यादव, किशोर बैरागी, हेमंत हरित, मदन गुर्जर, मनोष चौरसिया, जीशान कुरेशी, लोकेश चांगल आदि उपस्थित थे।

आज ही बुक करें अपना **Zelo** इलेक्ट्रिक स्कूटर, घर ले जाए

मात्र रु ~~45990/-~~ रु **38,990/-**

में वो भी 1 साल की बैटरी वारंटी के साथ

मात्र रु.38,990/- से इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज से शुरु ...

RTO मॉडल मात्र

रु ~~81000/-~~ रु **76000/-***

(माइलेज 80-100 कि.मी.) 3 साल बैटरी की वारंटी के साथ, आज ही बुक करवाए और पाए एक सोने का सिक्का ।

Zelo Electric Scooter

बंगला नं. 23, IDBI बैंक के सामने,
Lic रोड़, नीमच (म.प्र.)
मो. 940742399, 8770664866